राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14777/2023

नीलोफर बानू पुत्री श्री पीरू खान पत्नी स्वर्गीय श्री अमीन खान, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मस्जिद के पास मावली जिला उदयपुर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सचिव कृषि प्रबंधन संस्थान भवन दुर्गापुर जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से कृषि प्रबंधन संस्थान भवन दुर्गापुर जयपुर राजस्थान।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री दीपक चांडक

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>27/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन के अनुसार शिक्षक ग्रेड III, लेवल-I के पद के लिए ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के बजाय ईडब्ल्यूएस महिला विधवा श्रेणी में उनकी उम्मीदवारी पर विचार करें।

2. प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य यह है कि शिक्षक ग्रेड III, लेवल-I के पद के लिए दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन (अनुलग्नक 1) के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी श्रेणी "ओबीसी-एनसीएल" का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया। ओबीसी श्रेणी से प्रवेश पत्र जारी किया गया और याचिकाकर्ता 25.02.2023 को

आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुई। परिणाम घोषित किया गया। शॉर्टलिस्ट किए गए योग्य उम्मीदवारों की सूची 26.05.2024 को जारी की गई। याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुई। दस्तावेज सत्यापन के बाद, दिनांक 01.09.2023 को एक सूची जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ता के नाम के सामने एक टिप्पणी थी "शपथ पत्र के साथ ओबीसी-एनसीएल की आवश्यकता है।" हालाँकि, खुद को ईडब्ल्यूएस महिला विधवा श्रेणी का बताते हुए, उसने दिनांक 06.09.2023 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जब प्रतिवादियों ने 31.08.2023 को अंतिम परिणाम जारी किया, तो उसका नाम चयन सूची में नहीं था। इसलिए, यह याचिका।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार करने का पर्याप्त अवसर था। सभी उम्मीदवारों को 19.01.2023 तक अपने विकल्पों में सुधार/परिवर्तन/संशोधन करने का अवसर दिया गया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने कोई सुधार नहीं किया। इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई विवरण बताना भूल जाता है, तो वह आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि से 7 दिनों के भीतर 300 रुपये का भुगतान करके मूल ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का अवसर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, जब याचिकाकर्ता को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, तो वह उस समय भी अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार याचिकाकर्ता के पास गलती सुधारने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन उसने इसका लाभ नहीं उठाया। इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए और इसे अंतहीन रूप से खुला नहीं छोड़ा जा सकता है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष एक संक्षिप्त विवाद यह उभर कर आया है कि क्या याचिकाकर्ता श्रेणी में परिवर्तन की मांग कर सकती है, वह भी परिणाम घोषित होने के बाद, इस आधार पर कि उसकी असावधानी के कारण उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत श्रेणी भर दी थी?

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामलों में जहां यह मानवीय भूल का मामला है, जो कंप्यूटर के माउस पर क्लिक करने की असावधानी से उत्पन्न हुआ है, एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है और ऐसे उम्मीदवार को लाभ दिया जा सकता है। हालांकि, यहां ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता ने जानबूझकर फॉर्म भरते समय ओबीसी की श्रेणी का चयन किया है। यह उसके आचरण से पता

चलता है, क्योंकि उसने उसके बाद कभी भी कोई कदम नहीं उठाया, जब उसे एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें लिखित परीक्षा देने के लिए उसकी श्रेणी स्पष्ट रूप से लिखी गई थी। इतना ही नहीं, लिखित परीक्षा के बाद भी, उसने कभी नहीं बताया कि उसने अनजाने में ओबीसी का विकल्प चुना है, जबकि उसे ईडब्ल्यूएस विधवा श्रेणी में आवेदन करना चाहिए था।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि शायद याचिकाकर्ता को यह लग रहा था कि ईडब्ल्यूएस विधवा की तुलना में ओबीसी श्रेणी में उसके सफल होने की संभावना अधिक है। इसलिए, उसने जानबूझकर और रणनीतिक रूप से परिणाम घोषित होने तक अपनी तथाकथित गलती को उजागर नहीं किया। जब परिणाम घोषित हो गया और वह ओबीसी श्रेणी में असफल रही, तो अचानक पलटवार करते हुए उसने यह दलील दी कि उसने गलत श्रेणी का चयन किया था।

8. इस संदर्भ में, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने भी सोनल त्यागी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7840/2019, दिनांक 12.07.2019 को निर्णीत मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है। प्रासंगिक निम्नलिखित है:-

> "5. इस मामले में, याचिकाकर्ता ने 51 अंक प्राप्त किए; सामान्य श्रेणी के लिए कट-ऑफ 60 था। यह महसूस करने के बाद कि उसका चयन होने की संभावना नहीं है, उसने अदालत से संपर्क किया और पाया कि तलाक की श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक 43 थे।
>
> 6. यदि ऐसी परिस्थितियों में राहत दी जानी थी, तो मेरिट सूची में शामिल, तलाकशुदा श्रेणी के लोग और जिन्होंने खुद को इस तरह घोषित किया था, निश्चित रूप से विस्थापित हो जाएंगे। यह इस अदालत को कोई राहत देने से रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वाग्रह है।"

9. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।